आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 29.11.2024 समय : 1905

<><><><><><>

- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत देशभर में पच्चीस हजार जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है।
- दक्षिण अंडमान ज़िले में सभी भूमि–संबंधी कार्यों के लिए ऑनलाइन भूमि पंजीकरण प्रणाली में सुधार किया जा रहा है।
- पीएमईजीपी के तहत मध्योत्तर अंडमान में जागरूकता और जन–शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जल्द ही स्नातक छात्रों के लिए डिग्री पाठ्यक्रमों की अवधि कम करने या उसे बढ़ाने का विकल्प प्रदान करेगा।
- दक्षिण अंडमान ज़िला प्रशासन की ओर से आज मीठाखाड़ी और मंगलूटान में अभियान चलाकर चौदह हजार सात सौ वर्ग मीटर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

<><><><><><>

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना–पीएमबीजेपी के अंतर्गत मार्च दो हजार सत्ताईस तक देशभर में पच्चीस हजार जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि इस वर्ष मार्च के अंत तक कुल चौदह हजार एक सौ इक्कतीस जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए विभिन्न स्तरों पर नौ सौ नब्बे आवेदनों की जांच की जा रही हैं। आज दो सौ छः दवा निर्माता दवाइयों, सर्जिकल उपकरणों, न्यूट्रास्युटिकल्स और आयुर्वेदिक उत्पादों की आपूर्ति के लिए पीएमबीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया से जुड़े हैं।

<><><><><><>

दक्षिण अंडमान ज़िले में उप–पंजीयक और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की की ओर से द्वीपसमूह में सभी भूमि–संबंधी कार्यों के लिए ऑनलाइन भूमि पंजीकरण प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सार्वजनिक सुविधा में सुधार और पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली में सभी प्रकार के कार्यों को पंजीकृत करने के लिए उपलब्ध ऑनलाइन पंजीकरण स्लॉट की संख्या अब प्रतिदिन आठ स्लॉट से बढ़ाकर बारह स्लॉट कर दी गई है। इसका उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना, सुचारू पंजीकरण सेवाएँ सुनिश्चित करना और सभी कार्यों का समय पर निपटान करना है। यह सुविधा दो दिसंबर से सभी कार्य दिवसों में लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। आम जनता आधिकारिक एन जी डी आर एस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने पंजीकरण स्लॉट बुक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उप–पंजीयक और अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

<><><><><><>

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम और सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं तथा उद्योग विभाग और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से कियान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए मध्योत्तर अंडमान में बेरोजगार मुक्त यूटी अभियान के तहत जागरूकता और जन–शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मध्योत्तर अंडमान ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण विकास, पशुपालन और पशुचिकित्सा विभाग, कृषि, मत्स्य, एन वाई के और बैंक के सहयोग से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार गतिविधियों में शामिल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है और मौके पर ही चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और उसके लाभ के बारे में जानकारी देना है, ताकि वे उन योजनाओं का लाभ उठा सके। कार्यक्रम में युवाओं को दस्तावेजीकरण, ऑनलाइन ऋण आवेदन जमा करना और परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस सिलसिले में दो दिसम्बर को सुबह दस बजे से पंचायत हॉल नीलाम्बुर में, दो दिसम्बर को साढ़े तीन बजे कदमतला पंचायत हॉल में, तीन दिसम्बर को सुबह दस बजे बकुलतला और शाम चार बजे हरिनगर ग्राम पंचायत में, चार दिसम्बर को सुबह साढ़े दस बजे दानापुर में और शाम चार बजे किशोरीनगर पंचायत में, पांच दिसम्बर को कालीघाट पंचायत में सुबह दस बजे और शाम तीन बजे डिगलीपुर के गणेश नगर ग्राम पंचायत में कार्यक्रम रखा गया है। ज़िले के इच्छुक बेरोज़गार युवा, जो निर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्राप्त कर स्वरोज़गार स्थापित करना चाहते हैं, उनसे निर्धारित तिथि और समय पर इन कार्यक्रमों में भाग लेने को कहा गया है।

<><><><><><>

राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के कार्यकारी संपादक और अवकाश प्राप्त कमोडोर देबेश लाहिरी और उनके दल ने कल राज निवास में उप–राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी से मुलाकात की। उनका यह दल श्री विजयपुरम और स्वराज द्वीप में कानी केबल परियोजना और बुनियादी ढांचे के आंकलन के लिए द्वीपसमूह के दौरे पर है।

<><><><><><><>

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जल्द ही स्नातक छात्रों के लिए डिग्री पाठ्यक्रमों की अवधि कम करने या उसे बढ़ाने का विकल्प प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने त्वरित और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने मीडिया को बताया कि त्वरित डिग्री कार्यक्रम से छात्रों को प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करके कम समय में तीन साल या चार साल की डिग्री हासिल करने का मौका मिलेगा। त्वरित और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम के तहत छात्रों को सामान्य अवधि के कार्यक्रम के तहत क्रेडिट मिलेंगे। विस्तारित डिग्री कार्यक्रम के तहत छात्र अपनी डिग्री की समय सीमा को दो सेमेस्टर तक बढ़ा सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान इन कार्यक्रमों के लिए छात्रों की पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए समितियों का गठन करेंगे। संस्थान स्वीकृत प्रवेश सीमा के दस प्रतिशत तक इस विशेष डिग्री कार्यक्रम के लिए निर्धारित कर सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान स्टैंडर्ड पीरियड के बजाय चुनी गई अवधि में कार्यक्रम पूरा करने पर छात्रों को डिग्री जारी करेंगे। पहले या बाद में पूरी की गई स्नातक डिग्री को भी रोजगार और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए सामान्य अवधि की डिग्री के बराबर माना जाएगा।

<><><><><><><>

डीब्रेट में भारी वाहन चालक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम प्रशासन के भर्ती पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार के उत्तीर्ण न होने के कारण कौशल विकास और ट्रेड परीक्षा रद्द कर दी गई है। नई रिक्ति सूचना जल्द जारी की जाएगी।

<><><><><><><>

बंगाल एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स– बानी की ओर से द्वीपसमूह में बंगाली सेटेलेमेंट के पचहत्तर वर्ष पूरा होने के सिलसिले में प्लेटिनम जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। जोड़ाकिलान के राधा गोविन्द मंदिर में एक दिसम्बर को सुबह नौ बजे से रात्रि आठ बजे तक कार्यक्रम आयोजित की जाएगी।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान ज़िला प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज मीठाखाड़ी और मंगलूटान में अभियान चलाकर चौदह हजार सात सौ वर्ग मीटर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। मीठाखाड़ी में, आस–पास के ग्रामीणों द्वारा छः सौ वर्ग मीटर भूमि पर लगाए गए अनधिकृत बाड़ को हटाया गया। इसके अलावा अतिक्रमण के तीन अन्य मामलों को भी निपटाया गया, जिसमें सौ वर्ग मीटर सरकारी राजस्व भूमि पर बाड़ और केले तथा सुपारी के पौधे लगाए गए थे, नौ सौ वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अनधिकृत बाड़ लगाई गई थी और बारह वर्ग मीटर के पार्किंग शेड को हटाया गया। इस बीच, मंगलुटान में, अंडमान सी फूड कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा अतिक्मण किए गए छः हजार छः सौ वर्ग मीटर सरकारी भूमि को अतिक्मणकारियों से मुक्त कराया गया। जिला प्रशासन ने आम जनता से ज़िला नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने या व्हाट्सएप के माध्यम से अतिक्रमण या अनधिकृत निर्माण की सूचना देने का अनुरोध किया है।

<><><><><><><>

फरारगंज उप–प्रभाग के तहत शोल बे–फरारगंज फीडर और पैनल पांच फीडर में बम्बूफ़्लाट जेट्टी के नजदीक एल टी लाईन को बदलने और एच टी तथा एल टी लाईन में रखरखाव का कार्य किए जाने के चलते कल बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। कटौती सुबह आठ बजे से दिन में दो बजे तक की जाएगी। यह कार्य मौसम पर निर्भर करेगा।

<><><><><><><>